आर. एन. आई. नं. UPHIN/2010/32566 डाक. पंजीयन. संख्या– SSP/LW/NP-311

अद्भुत समाचार

निष्पक्ष एवं निर्भीक हिन्दी साप्ताहिक

हर ख़बर पर पैनी नज़र

वर्ष : 16 अंक : 34 लखनऊ, रविवार 14 दिसम्बर 2025 सा 20 दिसम्बर 2025 तक पृष्ठ–8 मूल्य : एक रूपया

जनगणना के नतीजे विकास के लिए दिशा–निर्देशक साबित होंगे : अमित शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि जनगणना २०२७ के नतीजे देश के विकास के लिए नए दिशा–निर्देशक की तरह काम करेंगे, क्योंकि ये भारत की नवीनतम जनसंख्या से जुड़े आंकड़ों को अधिक सटीकता के साथ प्रतिबिंबित करेंगे। शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय कवायद के लिए ११,७१८.२४ करोड़ रुपये आवंटित करते हुए जनगणना २०२७ के बजट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने 'एक्स' पर एक पोस्ट कर कहा, ''आंकड़ों में सटीकता मोदी जी के सुशासन और विकास के लाभों को हर वर्ग के नागरिकों तक पहुंचाने के दृष्टिकोण को गति देगी, जिससे सबका साथ, सबका

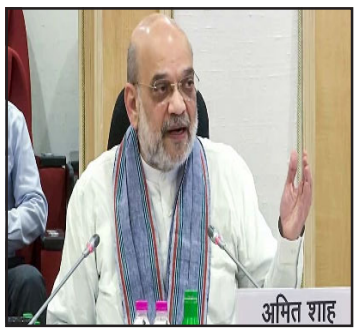

विकास का नारा अमृत काल में नए भारत की एक भव्य वास्तविकता बन जाएगा।'' प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में जनगणना कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जो अपनी तरह की पहली डिजिटल जनगणना होगी। स्वतंत्रता के बाद से जनगणना का १६वां संस्करण पहली बार जाति आधारित गणना भी करेगा और नागरिकों को स्वयं गणना करने का विकल्प भी प्रदान करेगा। देश भर में कोविड–१९ महामारी के प्रकोप के कारण २०२१ में होने वाली यह दशकीय कवायद स्थगित कर दी गई थी। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। इसके तहत अप्रैल से सितंबर २०२६ तक मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का काम होगाय और फरवरी २०२७ में जनसंख्या गणना की जाएगी। लगभग ३० लाख जनगणनाकर्मी प्रत्येक घर का दौरा करेंगे और घर–परिवार सूचीकरण, आवास गणना और जनसंख्या गणना के लिए अलग–अलग प्रश्नावली के माध्यम से सर्वेक्षण करेंगे। गृह मंत्री ने बताया कि लद्दाख, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना सितंबर २०२६ में की जाएगी। अमित शाह ने मिलिंग कोपरा और बॉल कोपरा के एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि के फैसले का भी स्वागत किया। शाह ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मिलिंग कोपरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में १२६ प्रतिशत और बॉल कोपरा के लिए १२७ प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी है (२०१४ की तुलना में)। उन्होंने कहा कि यह फैसला नारियल उत्पादक किसानों के लिए समृद्धि का नया युग लाएगा। गृह मंत्री ने कैबिनेट द्वारा कोल सेतु नामक कोयला लिंकेज नीति सुधारों को मंजूरी दिए जाने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से प्रधानमंत्री मोदी द्वारा परिकल्पित बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के ष्टिकोण को नई गति मिलेगी। इस कदम से घरेलू उद्योगों के लिए कोयला आसानी से उपलब्ध होगा, आयात बिल में कमी आएगी और धुले हुए कोयले का निर्यात संभव हो पाएगा।

उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी ने दाखिल किया नामांकन, रविवार को होगा औपचारिक ऐलान

लखनऊ। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया

और ऐसा करने वाले वे एकमात्र उम्मीदवार थे। राज्य अध्यक्ष की औपचारिक घोषणा केंद्रीय चुनाव अधिकारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा रविवार को की जाएगी। चौधरी ने लखनऊ स्थित अपने कार्यालय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक तथा जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा राज्य चुनाव अधिकारी महेंद्र नाथ पांडे और केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक विनोद तावड़े को नामांकन पत्र सौंपे। पंकज चौधरी के लिए प्रस्ताव रखने वालों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक, स्मृति ईरानी, ''स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, सुरेश खन्ना और बेबी रानी मौर्य शामिल हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल करने के बाद चौधरी ने कहा, ष्नामांकन दाखिल कर दिया गया है। जांच चल रही है। कल जब घोषणा होगी, तब कुछ और कहा जा सकेगा. .. कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में हमें जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, हम उसे पूरी निष्ठा से निभाते हैं...।' पीयूष गोयल ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया अभी पूरी हुई है। बाकी की प्रक्रिया कल दोपहर को होगी। आगे की योजना उस समय घोषित की जाएगी। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चुनाव पर मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, 'पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। केवल एक उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्रों की जांच चल रही है और आधिकारिक घोषणा कल की जाएगी। हम पंकज चौधरी के पक्ष में थे। जिला टीमों, विधायकों, एमएलसी, सांसदों, माननीय मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं सहित कई लोग उपस्थित थे और उन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया।' महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सात बार सांसद रहे चौधरी कुर्मी समुदाय से आते हैं, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) में वर्गीकृत किया गया है। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का विश्वसनीय सहयोगी माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ओबीसी समुदाय में कुर्मी समुदाय का काफी दबदबा है और २०२४ के लोकसभा और २०२२ के विधानसभा चुनावों में उन्होंने राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रति अपना झुकाव दिखाया था। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने कुर्मी समुदाय के नेताओं को तीन बार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है– पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह और स्वतंत्र देव सिंह।

प्रयागराज माघ मेला २०२६: १५ करोड़ श्रद्धालुओं की उम्मीद, भव्य आयोजन की तैयारियां तेज

लखनऊ। प्रयागराज में २०२६ के माघ मेले के लिए व्यापक तैयारियां चल रही हैं। उत्तर प्रदेश प्रशासन को भारी संख्या में तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के आने की उम्मीद है। प्रयागराज संभागीय आयुक्त सौम्या अग्रवाल के अनुसार, आगामी माघ मेला पिछले वर्षों की तुलना में अधिक भव्य होने की उम्मीद है, जिसमें लगभग १५ करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। यह वार्षिक धार्मिक आयोजन ३ जनवरी, २०२६ से शुरू होकर १५ फरवरी तक चलेगा, जो मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि सहित कई शुभ स्नान दिवसों के साथ मेल खाता है। माघ मेला पारंपरिक रूप से त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है, जो गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम है, जहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने आते हैं। एएनआई से बात करते हुए संभागीय आयुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि तीर्थयात्रियों की संभावित भारी संख्या को देखते हुए इस वर्ष माघ मेले का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि एक और सेक्टर का निर्माण किया जा रहा है, जबकि इस बार पोंटून पुलों की संख्या सात होगी। कुंभ मेले की तरह ही यातायात अनुमानों के आधार पर उचित आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई हैं। अनुमान का विस्तृत विवरण देते हुए उन्होंने आगे कहा कि वर्तमान रुझानों को ध्यान में रखते हुए और अस्थायी आबादी को भी शामिल करते हुए, तीर्थयात्रियों की संभावित संख्या काफी अधिक है, जिससे माघ मेला २०२६ में लगभग १५ करोड़ आगंतुकों का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने आगामी मेले के प्रमुख दिनों की तिथियां साझा करते हुए अपना बयान समाप्त किया। उन्होंने

आधिकारिक तौर पर कहा, 'मकर संक्रांति १५ जनवरी को है, मौनी अमावस्या १८ जनवरी को है, और इसके साथ ही मेला १५ फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ समाप्त होगा।' इससे पहले, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बताया था कि आगंतुकों की अनुमानित संख्या लगभग १२ से १५ करोड़ होगी। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कई कल्पवासी पौष पूर्णिमा के लिए जनवरी में आते हैं, और लगभग २० से २५ लाख आगंतुक पूरे डेढ़ महीने तक छह महत्वपूर्ण दिनों में स्नान करने के लिए रुकते हैं।

सम्पादकीय

राहुल गांधी की चार मांगें

चुनाव सुधार पर बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार से तीन सवाल पूछे। ये वो सवाल हैं, जो सार्वजनिक दायरे में लगातार अहम बने रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने पूछा कि निर्वाचन आयुक्तों की चयन समिति से भारत के प्रधान न्यायाधीश को क्यों हटाया गया? यह प्रावधान क्यों किया गया कि पद पर रहते हुए निर्वाचन आयुक्त जो भी कार्य करेंगे, उनको लेकर उन पर कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकेगी? यह कानूनी व्यवस्था क्यों की गई कि चुनाव के सिर्फ ४५ दिन बाद निर्वाचन आयोग सीसीटीवी और उससे हासिल डेटा को नष्ट कर सकेगा? केंद्र अगर चाहता है कि जनमत के एक बड़े हिस्से की निगाह में चुनावों की लगातार घट रही साख को बहाल किया जाए, तो उसे इन प्रश्नों के विश्वसनीय उत्तर जरूर देने चाहिए। दरअसल, गांधी ने जो चार मांगें रखीं, अगर उनके प्रति सरकार सकारात्मक रुख अपनाए, तो देश की चुनाव प्रक्रिया को और विवादित होने से बचाया जा सकेगा। ये मांगें हैः चुनाव से कम–से–कम एक महीना पहले मशीन–रीडेबल वोटर लिस्ट जारी हो, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून वापस लिया जाए, विपक्ष को ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक हो, तथा चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून बदला जाए। किसी तर्क से नहीं कहा जा सकता कि ये मांगे नाजायज हैं। चुनाव प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दल समान हितधारक हैं। इसलिए इन मांगों का औचित्य स्वयंसिद्ध है। "वोट चोरी" के विपक्ष के इल्जाम में दम है या नहीं– यह अवश्य बहस का विषय है। निष्पक्ष नजरिए से इस दावे को स्वीकार करना कठिन है कि भाजपा की जीत सिर्फ "वोट मैनेजमेंट" से हो रही है। यह बात भी अपनी जगह सही हो सकती है कि कई दलों ने "वोट चोरी" की कहानी को अपनी नाकामियों को ढकने का बहाना बना लिया है। मगर, यह भी सच है कि उपरोक्त प्रश्नों से इस नैरेटिव को वजन मिला है। इसलिए लोगों के मन में तैर रहे संदेहों का निवारण किया जाना चाहिए। ऐसा ना होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिनकी ओर नेता विपक्ष ने भी इशारा किया।

एनआरसी का छिपा रूप है एसआईआर : अखिलेश यादव

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की कवायद की निंदा करते हुए कहा कि यह ''एनआरसी का छिपा हुआ रूप'' है और भाजपा विरोधी मतदाताओं को हटाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। अखिलेश शनिवार को होने जा रहे 'विजन इंडिया – एआई शिखर सम्मेलन' में भाग लेने के लिए हैदराबाद आए हैं। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और बीआरएस नेताओं के साथ भी बैठकें कीं, जिनमें इसके कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव भी शामिल थे। अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि निर्वाचन आयोग को बड़े पैमाने पर नाम हटाने की अनुमति देने के बजाय मतदाता भागीदारी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ से अधिक मतों के कटने का खतरा है।'' सपा प्रमुख ने कहा, ''यह एसआईआर नहीं है। यह एसआईआर के वेश में एनआरसी (राष्ट्रीय नागरिक पंजी) है। वे सीधे एनआरसी लागू नहीं कर सके। अब वे एनआरसी लेकर आए हैं। अगर एनआरसी कभी लागू होता है, तो कौन से दस्तावेज देने होंगे? वही कागजात पेश करने होंगे।

फंदे से लटका मिला सिपाही, पुलिस ने जांच शुरू की

लखनऊ के आलमबाग इलाके में शुक्रवार शाम एक सिपाही ने कथित तौर पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें शाम करीब छह बजे सूचना मिली कि आलमबाग इलाके में किराए के एक मकान में एक सिपाही ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने बताया कि मृतक की पहचान अलीगढ़ जिले के पिसावा गांव के निवासी आरक्षी बाल किशन (२८) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि उनकी भर्ती २०१६ बैच में हुई थी और वह वर्तमान में आलमबाग में तैनात थे। उन्होंने बताया कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

नशे से बचकर ही खुद को और देश के भविष्य को बचा पाएंगे युवा : सीएम योगी

लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज युवाओं के सामने दो चुनौतियां हैं। एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों ही नशे से बचना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे, उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के प्रेक्षागृह में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के ६३वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित मुख्य महोत्सव की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का स्वागत करते हुए सीएम योगी ने युवाओं को मोबाइल फोन के नशे से दूर रहने की सलाह दी। एक शिक्षक और अभिभावक के रूप में मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि नशा माफिया तेजी के साथ युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में लेने का कुत्सित प्रयास करता है। अकादमिक संस्थाओं को भी इसके प्रति उतना ही अलर्ट रहना पड़ेगा। युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि देश का दुश्मन किसी न किसी रूप में आपके बीच में घुसना चाहता है। उसको हम अवसर नहीं दें। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्मार्टफोन पर युवाओं का अत्यधिक समय खर्च हो रहा है, इसको कम करना होगा। उन्होंने युवाओं को समझाया, हालांकि एकाएक यह कर पाना कठिन होगा, इसलिए धीरे–धीरे कम करिए। आवश्यक हो तभी आधा या एक घंटा तक ही आप मोबाइल फोन का इस्तेमाल करिए। समय

तय करिए कि मुझे जब आवश्यक बात करनी है तभी बात करूंगा, अनावश्यक नहीं। स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग आपकी आंख की साइट को प्रभावित करेगा। मस्तिष्क को कुंद कर देगा, बुद्धि, विवेक और शारीरिक क्षमता को भी यह पूरी तरह कमजोर कर देगा। इसलिए स्मार्टफोन से जितना बच सकते हैं, बचने का प्रयास करना चाहिए। समय और तकनीक के साथ चलते हुए भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करने की सीख देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक्स के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। हममें से कोई व्यक्ति उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकता। हमें करना भी नहीं चाहिए। हमें उस मानसिकता से भी उबरना पड़ेगा कि तकनीक आएगी तो रोजगार के अवसर कम करेगी। यह तथ्य सही नहीं है, बल्कि तकनीक आएगी और रोजगार के नए अवसर अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हमें अपने आप को उसके अनुरूप शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करना होगा। समारोह में मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा कि जीवन में जीतता वही है जो हिम्मत नहीं हारता है और धैर्य बनाए रखता है। जीवन में हार तभी होती है जब हमारा दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। दूसरों को कोसने की बजाय, अंधकार को धिक्कारने की बजाय, यदि हम 'आओ मिलकर दीया जलाएं' का काम करने लग जाएं, हर व्यक्ति मिलकर एक साथ आगे बढ़ने लग जाए तो कहीं भी अंधकार नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क का महत्व समझाते हुए कहा कि यह केवल एक गेम में नहीं बल्कि पूरी जनरेशन में उपयोगी होता है। हमें अपने आप को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से, टीम वर्क से जोड़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह भी याद रखना होगा कि शॉर्टकट का रास्ता कभी जीवन में सफलता नहीं प्रदान कर सकता है। हर व्यक्ति और संस्था को हमेशा इस बात के लिए तैयार होना होगा कि तकनीक जितना आसान जीवन को कर रही है, उतनी ही चुनौतियां और कठिनाई भी हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। युवाओं और अकादमिक संस्थाओं को उसके प्रति अपने आप को तैयार करना होगा।

उच्च न्यायालय ने आरएमएल के पास शराब की दुकान का लाइसेंस जारी करने और खुलेआम पीने पर नाराजगी जताई

लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के पास शराब की दुकान का लाइसेंस जारी करने और दुकान के सामने खुलेआम शराब पीने पर कड़ी नाराजगी जताई है। पीठ ने अपने पिछले आदेश पर पुलिस द्वारा अनुपालन न करने पर कहा, हमें आश्चर्य है कि अधिकारी अदालत के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और लगता है कि उन्हें अवमानना घ्का दोषी ठहराये जाने के बाद ही वे आदेशों का पालन करने के लिए तैयार होंगे। इस तरह का लापरवाह रवैया हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने स्थानीय निवासी दिनेश यादव और अन्य द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि वे डॉ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के सामने वाली कॉलोनी में रहते हैं और मायर्स अस्पताल भी पास में ही स्थित है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि आबकारी विभाग ने मित्रलेखा वर्मा को शराब की दुकान

का लाइसेंस जारी किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि शराब की दुकान के बाहर उपद्रवियों और शराबियों की लगातार भीड़ से निवासियों को काफी असुविधा होती है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा घ्घने दलील दी कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मनोज कुमार द्विवेदी मामले में उच्चतम न्यायालय के २००८ के फैसले के अनुसार, किसी अस्पताल, मंदिर या आवासीय कॉलोनी के १०० मीटर के दायरे में शराब की दुकान का लाइसेंस जारी नहीं किया जा सकता है। मेहरोत्रा ने अपनी दलील में कहा कि हालांकि, इस मामले में आबकारी विभाग ने मायर्स अस्पताल से ५३ मीटर के भीतर शराब की दुकान का लाइसेंस जारी किया है, जो उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया गया कि शराब की दुकान के बाहर खुलेआम शराब पी रहे लोगों की भीड़ आसपास के लोगों और राहगीरों के लिए जीवन मुश्किल बना रही है और साथ ही कानून–व्यवस्था का संकट भी पैदा कर रही है। मामले की अगली सुनवायी २७ जनवरी को होगी।

आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाएगी उप्र सरकार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार आयुष उद्योग को बढ़ावा

देने के लिए नई आयुष योजना लाने जा रही है। शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया है कि प्रदेश में आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए योजना में निवेशकों को विभिन्न तरह की सहूलियतें दी जाएंगी। बयान में कहा गया है कि योजना में आयुष अनुसंधान को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है ताकि प्रदेश को आयुष अनुसंधान का केंद्र बनाया जा सके। बयान में कहा गया है कि नई योजना के तहत प्रदेश में आयुष अस्पतालों में मरीजों के इलाज की व्यवस्था को और भी बेहतर बनाया जाएगा, साथ ही आयुष विभाग को लगातार विकसित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।

युवती ने फेसबुक पर 'लाइव' आकर फंदा लगाया, मौत

लखनऊ। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में २४ वर्षीय एक युवती ने फेसबुक पर 'लाइव' आकर कथित तौर पर फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। विभूति खंड थाना प्रभारी अमर सिंह ने बताया कि युवती मूलरूप से आंबेडकर नगर जिले की रहने वाली थी और लखनऊ में किराए के कमरे में रहती थी। युवती ने आंबेडकर नगर जिले के एक स्थानीय पत्रकार के खिलाफ तथा सेना में कार्यरत एक व्यक्ति के खिलाफ भी मामला दर्ज कराया था। सेना के व्यक्ति पर आरोप था कि उसने शादी का झांसा देकर करीब पांच से सात महीने तक उसे धोखा दिया। पुलिस के अनुसार, बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे युवती फेसबुक पर 'लाइव' आईं। इसकी सूचना मेटा ने पुलिस नियंत्रण कक्ष को दी। थाना प्रभारी ने बताया कि कमरा अंदर से बंद था, इसलिए दरवाजा तोड़ने में समय लगा। युवती को तुरंत डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि लाइव वीडियो में युवती को यह कहते सुना जा सकती है कि वह नाटक नहीं कर रही, बल्कि वास्तव में आत्महत्या कर लेगी। हालांकि, उसने किसी का नाम नहीं लिया।

बंद मकान को चोरों ने खंगाला, बटोरा माल

सरोजनीनगर। बिजनौर थाना क्षेत्र में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाया। चोरों ने जेवर व नकदी समेत करीब सवा लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। शनिवार को पीड़ित महिला ने चोरी की सूचना दी। पुलिस घटनास्थल की छानबीन करने के साथ सीसीटीवी कैमरों के मदद से जांच कर रही है।बिजनौर के रहीमाबाद निवासी जानकी ने बताया कि बेटा अमित दिल्ली में रहकर नौकरी करता है। शुक्रवार को वह घर में ताला बंद कर अपनी बीमार मां को देखने उन्नाव स्थित मायके गई थी। शनिवार सुबह पीड़िता के बगल में रहने वाली उसकी देवरानी अंजू ने ताले टूटे देख सूचना जानकी को दी।इसके बाद घर पहुंची जानकी ने देखा तो अंदर कमरे व संदूक के ताले टूटे होने के साथ घर का सारा सामान बिखरा पड़ा मिला। साथ ही संदूक में रखे करीब १ लाख रुपये कीमत के गहने और २० हजार रुपये गायब मिले।

मकान की दीवार में सेंध लगाकर लाखों की चोरी

लखनऊ। थाना क्षेत्र के अटारी गांव व कस्बा में चोरों ने दो घरों को निशाना बनाया। एक मकान की दीवार में सेंध लगायी तो दूसरे घर में छत के रास्ते घुसकर वारदात को अंजाम दिया। शनिवार सुबह सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की। अटारी गांव निवासी लल्लू प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार रात खाना खाने के बाद पत्नी मखाना के साथ घर के बाहर छप्पर के नीचे सो गया था। शनिवार सुबह आंख खुली। घर के अंदर प्रवेश करने के लिए दरवाजा खोलने का प्रयास किया तो अंदर से बंद था। घर के पीछे गए तो दीवार में सेंध लगी थी।दीवार फांदकर अंदर गए तो सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने बताया कि चोरों ने बक्से में रखे लगभग एक किलो चांदी के जेवर व ३५ हजार रुपये चोरी किए हैं। वहीं, कस्बा निवासी विनोद ने बताया कि शुक्रवार रात छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने चारपाई पर रखा मोबाइल व खूंटी पर टंगे बैग से ३० हजार, पैंट की जेब से दस हजार और अटैची से जेवर चोरी कर लिए। सुबह ड यल–११२ पर सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है।

अखिलेश के PDA की तोड़? यूपी BJP अध्यक्ष की रेस में है नाम, संसद में दीपेंद्र हुड्डा ने भी दे दी बधाई

लखनऊ। लोकसभा में चर्चा के दौरान कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी को बधाई दी। हुड्डा ने कहा कि आपकी पार्टी में पदोन्नती होने जा रही है, बधाई हो। सूत्रों की मानें तो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पंकज चौधरी को पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। चौधरी वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से लोकसभा सांसद हैं। चौधरी ओबीसी समुदाय से हैं और सूत्रों के अनुसार, वे उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार के रूप में उभरे हैं। भगवा पार्टी १४ दिसंबर को इस संबंध में घोषणा कर सकती है। वर्तमान में भूपेंद्र सिंह चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हैं। चौधरी राज्य में विधान परिषद के सदस्य हैं और एक प्रमुख जाट नेता हैं। उन्होंने अगस्त २०२२ में स्वतंत्र देव सिंह के बाद अध्यक्ष पद संभाला था। चौधरी ने २ दिसंबर को अमेठी में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा हमारे पास अब २.५ करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्य हैं। स्थानीय समिति के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ६८ जिलों में से हमने ८४ जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। हमारा संगठन नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच, भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतरे अन्य उम्मीदवारों में पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, राज्य मंत्री

स्वतंत्र देव सिंह और धर्मपाल सिंह शामिल हैं। चौधरी की तरह ज्योति भी ओबीसी हैं और निषाद समुदाय से संबंध रखती हैं। वर्मा भी ओबीसी हैं, लेकिन वे लोधी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों और २०२७ के विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, भाजपा द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी ओबीसी नेता को अपना अध्यक्ष नियुक्त करने की प्रबल संभावना है। २०२२ के चुनावों में, भाजपा ने ४०३ सदस्यीय विधानसभा में २५५ सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सत्ता बरकरार रखी। कुल मिलाकर, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने २०२२ के उत्तर प्रदेश चुनावों में २७३ सीटें जीती थीं। हालांकि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने में विफल रही, लेकिन उसने २०१७ के चुनावों की तुलना में अपने प्रदर्शन में सुधार किया और १११ सीटें जीतीं। साल २०२४ के चुनाव में बीजेपी को कुर्मी बहुल सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था। चुनाव में सपा ने जो ३७ सीटें जीती थीं। सपा ने २७ टिकट ओबीसी को दिए थे। उसने सबसे अधिक १० टिकट कुर्मी जाति को दिए थे। इनमें से सात ने जीत दर्ज की थी। जबकि बीजेपी ने २०१४ और २०१६ के लोकसभा चुनाव में कुर्मी और दूसरे गैर यादव ओबीसी वोटों के सहारे ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। सपा अपनी रणनीति के तहत बांदा को छोड़कर किसी भी ऐसी सीट पर कुर्मी प्रत्याशी नहीं उतारा था, जहां बीजेपी या अपना दल का उम्मीदवार कुर्मी हो। उसकी यह रणनीति कामयाब रही थी. बीजेपी इसका काट नहीं खोज पाई थी।

फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को गति देने और भवन निर्माण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से क्रय योग्य फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) से जुड़े नियमों में बड़ा संशोधन किया है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास (क्रय योग्य एफएआर शुल्क का निर्धारण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण) (प्रथम संशोधन) नियमावली–२०२५ को लागू कर दिया गया है। यह संशोधन ६ नवंबर २०२५ को राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा और प्रदेश के सभी विकास क्षेत्रों में लागू रहेगा। आवास विकास के प्रमुख सचिव पी. गुरुप्रसाद की ओर अधिसूचना जारी की गई है। शासनादेश के तहत अब केवल क्रययोग्य एफएआर ही नहीं, बल्कि प्रीमियम खरीदे जा सकने वाले एफएआर पर भी शुल्क वसूला जाएगा। इससे पहले शुल्क व्यवस्था केवल अतिरिक्त एफएआर तक सीमित थी। संशोधन के बाद अधिकतम अनुमन्य एफएआर में बेसिक एफएआर, खरीदे जा सकने वाला एफएआर और प्रीमियम खरीदे जा सकने वाला एफएआर तीनों शामिल होंगे। सरकार ने एफएआर शुल्क की गणना का फार्मूला भी स्पष्ट कर दिया है। इसके तहत अतिरिक्त अनुमन्य निर्मित क्षेत्रफल, बेसिक एफएआर, भूमि की वर्तमान सर्किल दर और भूमि उपयोग श्रेणी के अनुसार निर्धारित गुणांक के आधार पर

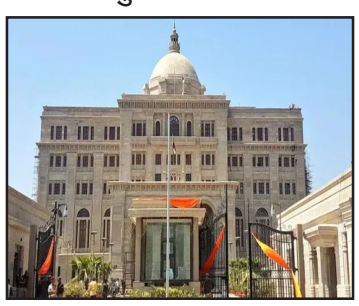

शुल्क तय होगा। भूमि की वर्तमान दर से आशय जिलाधिकारी द्वारा घोषित सर्किल दर से है। जहां सर्किल दर उपलब्ध नहीं होगी, वहां विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवासीय दर लागू होगी। सरकार का मानना है कि इस संशोधन से विकास प्राधिकरणों की आय बढ़ेगी और शहरी अवसंरचना के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही, निवेशकों और भवन निर्माताओं को स्पष्ट नियम मिलने से परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में सहूलियत होगी। संशोधित नियमों में भूमि उपयोग के अनुसार गुणांक भी तय किए गए हैं। वाणिज्यिक उपयोग के लिए खरीदे जा सकने वाले एफएआर पर ०.५० और प्रीमियम एफएआर पर १.०० गुणांक रखा गया है। मिश्रित उपयोग, कार्यालयध्संस्थागत भवनों, होटल, आवासीय (प्लॉटेड व समूह आवास), औद्योगिक तथा सामुदायिक व अवसंरचना सेवाओं के लिए अलग–अलग गुणांक निर्धारित किए गए हैं। इससे विभिन्न श्रेणियों में शुल्क निर्धारण में एकरूपता आएगी। शासनादेश में भुगतान की शर्तों को भी सरल बनाया गया है। यदि खरीदे या प्रीमियम एफएआर का कुल क्षेत्रफल १००० वर्ग मीटर से अधिक होता है, तो आवेदक को २५ प्रतिशत राशि अग्रिम जमा करनी होगी। शेष राशि १२ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ त्रैमासिक किस्तों में अधिकतम दो वर्षों में जमा की जा सकेगी। इसके लिए बैंक गारंटी या समतुल्य मूल्य की भूमि गिरवी रखने का प्रावधान भी किया गया है।

शाह और राहुल में तल्ख बहस

नई दिल्ली। चुनाव सुधारों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देने के क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बहस हो गई। बहस के दौरान अमित शाह बहुत तेज आवाज में कहा कि वे कब और कैसे बोलेंगे यह वे खुद तय करेंगे कोई और नहीं तय करेगा। शाह ने राहुल के उठाए सवालों का जवाब दिया लेकिन राहुल इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने संसद परिसर में मीडिया से कहा कि शाह ने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया। इससे पहले सदन में अमित शाह ने कहा, 'विपक्ष के नेता की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दूंगा। एक सादी वाली, एक एटम बम वाली और एक हाइड्रोजन बम वाली। हर सवाल का जवाब दूंगा'। इस पर राहुल गांधी ने उन्हें टोकते हुए कहा, 'शाह जी मैं आपको चौलेंज करता हूं। आप मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस क न्फ्रेंस पर चर्चा करें'। इस पर अमित शाह नाराज हो गए और तेज आवाज में उन्होंने कहा, '३०

साल से संसद या विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। आप नहीं'। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह की रिस्पांस डरा हुआ, घबराया हुआ है। हालांकि इसके बाद अमित शाह शांत हो गए और उन्होंने कहा, 'मैं उनके उकसावे पर नहीं आऊंगा। विषय पर बोलूंगा। मेरे भाषण में पहले, बाद में जो बोलना है मैं तय करूंगा। हमने तो नहीं कहा कि नेता विपक्ष झूठा बोल रहे हैं'। सदन से बाहर निकल कर राहुल गांधी ने शाह पर निशाना साधते हुए मीडिया से कहा, 'उन्होंने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। उनका जवाब पूरी तरह रक्षात्मक था। मैंने कहा था कि एक पारदर्शी वोटर लिस्ट दी जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था कि ईवीएम की आर्किटेक्चर सभी के सामने रखी जाए, लेकिन इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा'। राहुल ने कहा, 'मैंने कहा कि बीजेपी नेता हरियाणा और बिहार में वोट डाल रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने चीफ जस्टिस के बारे में भी कुछ नहीं कहा। चुनाव आयुक्त को पूरी इम्युनिटी दी जाती है। हम डरे नहीं हैं'।

कैबिनेट की बैठक में जनगणना के लिए ११,७१८ करोड़ रुपए की मंजूरी

नई दिल्ली। देश में पांच साल की देरी के बाद अप्रैल २०२६ में जनगणना शुरू होगी। जनगणना दो चरणों में होगी और पहली बार पूरी तरह से डिजिटली होगी। प्रध ानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जनगणना के लिए ११,७१८.२४ करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ३० लाख कर्मचारी डिजिटल जनगणना पूरी करेंगे। इसके लिए एक खास सॉफ्टवेयर बनाया गया है। उन्होंने बताया कि इस सॉफ्टवेयर का डिजाइन डेटा सुरक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि जनगणना दो चरण में होगी। पहला चरण अप्रैल से सितंबर २०२६ के बीच होगी, जिसमें घरों की लिस्टिंग और गिनती होगी। दूसरा चरण फरवरी २०२७ होगा, जिसमें आबादी की गिनती होगी। गौरतलब है कि हर १० साल पर होने वाली जनगणना २०२१ में होने वाली थी। परंतु कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। तब से यह लंबित है। बहरहाल, शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में और भी कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट ने कोलसेतु विंडो को मंजूरी दी है। इसके तहत अलग अलग औद्योगिक इस्तेमाल और निर्यात

के लिए कोल लिंकेज की नीलामी, सही पहुंच और रिसोर्स का सबसे अच्छा इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने २०२६ सीजन के लिए कोपरा यानी सूखे नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को मंजूरी दी। २०२६ सीजन के लिए फेयर एवरेज क्वालिटी मिलिंग कोपरा के लिए एमएसपी १२,०२७ रुपए प्रति क्विंटल और बॉल कोपरा के लिए १२,५०० रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है।

78 लाख रुपये का भूखंड बेचने के लिए जाली दस्तावेज बनाने के आरोप में छह लोग गिरफ्तार

बुलंदशहर। बुलंदशहर में कथित तौर पर जाली दस्तावेज बनाने और ७८ लाख रुपये की जमीन की फर्जी बिक्री का सौदा करने के आरोप में बृहस्पतिवार को एक महिला सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (शहर) शंकर प्रसाद ने बताया कि गाजियाबाद की रहने वाली उर्वशी गुप्ता ने नौ दिसंबर को काकोड थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि काकोडथानाक्षेत्र के बेलना गांव में उनकी जमीन धोखाधड़ी से बेच दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर काकोड़ थाने में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। इस संबंध में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला शामिल है। महिला आरोपी के बैंक खाते में १७.५० लाख रुपये के लेन–देन पर रोक लगा दी गयी है। पकड़े गए आरोपी बुलंदशहर के सतेन्द्र, कुलदीप और कर्मवीर, मथुरा के संतोष और संगीता व गौतमबुद्धनगर के राजकुमार हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने आपस में मिलकर संगीता चौधरी का फोटो लगाकर उर्वशी गुप्ता के नाम से फर्जी आधार कार्ड एवं पैन कार्ड बनवाए तथा उर्वशी गुप्ता की जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन दिल्ली के राहुल जैन के नाम कर दी गई। पुलिस अधीक्षक नगर प्रसाद ने बताया कि थाना ककोड़ क्षेत्र में जमीन का फर्जी तरीके से बैनामा करने वाला गिरोह प्रकाश में आया जिसमें छह लोग गिरफ्तार किए गए। इस संबंध में गाजियाबाद की उर्वशी की ककोड़ थानाक्षेत्र में जमीन है। उस जमीन को इस गिरोह द्वारा अपनी जमीन बताकर बैनामा किया गया और पैसे का लेनदेन हुआ। इसमें १७.५० लाख रूपये का लेनदेन हुआ था।

पुलिस ने आजीवन कारावास के सजायाफ्ता को ३७ साल बाद मप्र से गिरफ्तार किया

शाहजहांपुर। जिले की पुलिस ने साधु के भेष में रह रहे फरार आजीवन कारावास के सजायाफ्ता को आधुनिक विशिष्ट सर्विलांस तकनीक से ३७ साल के बाद मध य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने शुक्रवार को पीटीआई–को बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश उर्फ राजू के रूप में हुई, जिसे पुलिस ने आज गायत्री शक्तिपीठ, शिवपुरी (मध्यप्रदेश) से ३७ साल के बाद गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने घटना का ब्योरा देते हुए कहा कि थाना तिलहर में २८ अगस्त १९८६ में गंगा दीन (मुनीम) तथा ओमप्रकाश रस्तोगी अपने आभूषणों की दुकान पर घर से रिक्शा पर सवार होकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि इनके पास दुकान पर प्रयुक्त होने वाला तेजाब भी साथ में था, तभी रास्ते में राजेश उर्फ राजू आया और उनके साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान राजेश ने ओमप्रकाश के हाथ से तेजाब की बोतल छीनकर उन्हीं के ऊपर डाल दी जिससे ओमप्रकाश तथा गंगा दीन दोनों घायल हो गए थे। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी राजेश उर्फ राजू के विरुद्ध हत्या के प्रयास और अन्य संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया और न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद राजेश को ३० मई १९८८ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में उच्च न्यायालय से उसे जमानत मिल गई। द्विवेदी ने बताया कि इसके बाद आरोपी न्यायालय में कभी भी हाजिर नहीं हुआ और तब न्यायालय ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। पुलिस ने उसे आज गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी से ३७ साल के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसपी

ने बताया कि इस दौरान आरोपी राजेश पड़ोसी जनपदों के अलावा धार्मिक स्थलों पर रहता था और एक धार्मिक स्थल पर दो से चार माह तक रुकता। इसके बाद दूसरे धार्मिक स्थल पर पहुंच जाता था। इसी तरह यह आरोपी भेष बदलकर ३७ साल तक घूमता रहा और बाद में इसने गायत्री शक्तिपीठ शिवपुरी मध्यप्रदेश में अपना स्थायी ठिकाना बना लिया, जहां यह साधु के भेष में रह रहा था। द्विवेदी ने बताया की पुलिस विभाग के पोर्टल नाफीस आदि में अपराधियों के फिंगरप्रिंट रहते हैं। इसे शामिल करते हुए आधुनिक विशिष्ट सर्विलांस तकनीक से ३७ साल के बाद आरोपी को पकड़ा जा सका।

किशोरी से दुष्कर्म के लिए व्यक्ति को २० वर्ष की कारावास की सजा

मेरठ। जिले की एक विशेष प क्सो अदालत ने एक व्यक्ति को १३ वर्षीय किशारी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए २० वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र चौहान और अवकाश जैन ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) मोहम्मद बाबर खान की अदालत ने आरोपी व्यक्ति को शुक्रवार को दोषी ठहराते हुए २० वर्ष के कठोर कारावास और कुल ७०,००० रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि मामला २५ मार्च २०१६ का है, जब शिकायतकर्ता ने थाना ब्रहमपुरी में तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी १३ वर्षीय पुत्री को बहला–फुसलाकर ले गया और उसे धमकियां दीं। उन्होंने बताया कि इस आधार पर मुकदमा अपहरण और धमकी का पंजीकृत किया गया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने विवेचना के दौरान नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया और चिकित्सीय परीक्षण व बयान के आध ार पर मामले में दुष्कर्म और प क्सो कानून की धारा बढ़ायी गई। उन्होंने बताया कि इसके बाद आरोपपत्र अदालत में दाखिल किया गया और अदालत ने सुनवाई पूरी करके आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे सजा सुनाई।

डॉक्टर शिवनाथ मौर्य ने जिला अस्पताल ओयल में किया जटिल सर्जरी

लखीमपुर–खीरी। मरीज को पिछले १ साल से पेट में दर्द हो रही थी, खाना ठीक से नहीं खा पा रही थी जिसका इलाज मरीज के परिजन विभिन्न सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों से करा रहे थे लेकिन कोई आराम नहीं मिला, मरीज को बताया गया था कि उसके पेट में ट्यूमर है जिसकी वजह से मरीज के पेट में भारीपन, खाना ना खा पाना, पेट में दर्द एवं सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है मरीज कि जिला अस्पताल ओयल में संपूर्ण जांच कर दिनांक १२/१२/२०२५ मे सर्जन डॉ शिवनाथ मौर्य, डॉ **H D** भारती, डॉ अरविंद दीक्षित, डॉ आयुष एवं स्टाफ नर्स रेखा, अन्य **OT** स्टाफ के सहयोग से किया गया। मरीज का ट्यूमर इतना बड़ा था कि पूरे पेट पर दबाव दे रहा था, यह लगभग ५ किलो वजन का ट्यूमर निकाला गया उसके बाद मरीज को आईसीयू में शिफ्ट किया गया ऑपरेशन के बाद मरीज कि हालत स्थिर है।

राहुल ने उठाया प्रदूषण का मुद्दा

नई दिल्ली। कई दिन के हंगामे और वंदे मातरम व चुनाव सुधार पर चर्चा के बाद आखिरकार वायु प्रदूषण के मुद्दे का नंबर आया। शीतकालीन सत्र के दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को राहुल गांधी ने देश में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह देश के ज्यादातर बड़े शहरों की समस्या है। सरकार ने उनकी बात पर सहमति जताते हुए कहा कि वह हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार है। हालांकि चर्चा के लिए अभी कोई समय तय नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने शुक्रवार को वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाते हुए कहा, 'हमारे देश के ज्यादातर बड़े शहर जहरीली हवा की चपेट में हैं। लाखों बच्चे फेफड़ों की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है'। उन्होंने कहा, 'यह एक अहम मुद्दा है। मुझे पूरा यकीन है कि सरकार और हमारे बीच इस मामले पर एक सहमति होगी। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि प्रदूषण के कारण देश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है, उस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे'। सदन में मौजूद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, 'सरकार ने पहले दिन से ही अपना रुख साफ कर दिया था कि हम सभी अहम मामलों पर चर्चा करने के

लिए तैयार हैं। सरकार कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी के नेताओं से सुझाव लेने के लिए भी तैयार है'। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, 'मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम चर्चा को इस बात पर केंद्रित न करें कि हम क्या नहीं कर पाए और आप क्या नहीं कर पाए, बल्कि सीधे इस बात पर ध्यान दें कि हम भविष्य में भारत की जनता के लिए क्या करने जा रहे हैं, हमें कौन से कदम उठाने होंगे'। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, 'मेरा मानना है कि हम एक दूसरे पर दोषारोपण करने के बजाय, इस एक मुद्दे पर, जिस पर हम सहमत हैं, कोई असहमति नहीं है, चर्चा करें। चलिए, भारत की जनता के भविष्य के बारे में बात करते हैं'। राहुल ने कहा, 'यह कोई वैचारिक मुद्दा नहीं है। इस सदन में मौजूद हर सदस्य इस बात से सहमत होगा कि वायु प्रदूषण और इससे हमारे लोगों को होने वाला नुकसान ऐसी चीज है, जिस पर हम सभी मिलकर काम करना चाहेंगे'। संसद में शुक्रवार को तमिलनाडु के मुद्दे को लेकर थोड़ी देर गतिरोध बना। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने तमिलनाडु में दीपक जलाने की मांग पर हिंदुओं पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। उन्होंने तमिलनाडु की डीएमके सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, 'तमिलनाडु सनातन धर्म के विरोध का प्रतीक बन गया है। उनके मंत्री सनातन धर्म के विरुद्ध बयान देते हैं'। उनके इस आरोप पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही दो बजे तक स्थगित कर की गई।

'क्रिप्टो करेंसी' के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार

आगरा। में साइबर थाना पुलिस ने 'क्रिप्टो करेंसी' में निवेश के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी पुलिस ने दी। अपर पुलिस उपायुक्त (एसीपी) आदित्य ने बताया कि आरोपी की पहचान अजय के तौर पर हुई है और उसने अब तक १५०० लोगों से कथित तौर पर ठगी की है। उन्होंने बताया कि आरोपी अजय ने वैध क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफ र्म जैसा दिखने वाला एक वेबसाइट बनाया था और लोगों की रकम कई गुना करने का झांसा देकर निवेश कराया। उन्होंने बताया कि आरोप है कि वह लोगों से ठगी करने के लिए बड़े बड़े होटलों में सेमिनार आयोजित करता था। उन्होंने बताया कि आरोपी सेमिनार में कथित तौर पर कुछ लोगों के रुपये कई गुना करके वापस करना भी दिखाता था जिससे लोग झांसे में आकर लाखों रुपये निवेश करते थे। उन्होंने बताया कि आरोप है कि वेबसाइड पर सभी का डेटा रहता था जिसमें रकम कई गुना दिखायी जाती और लोगों का

भरोसा बना रहता था। उन्होंने बताया कि फिलहाल आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि उसके छह साथी अभी फरार हैं। आदित्य ने बताया कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस गिरोह के लोगों ने उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और दिल्ली में भी लोगों से कथित तौर पर ठगी की है।

अतिक्रमण हटेगा, बाधक बिजली पोल होंगे शिफ्ट, डीएम ने दिए सख्त निर्देश

लखीमपुर। जिला मुख्यालय की सबसे व्यस्त और सालों से जनता की माँग बनी सड़क डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर नए रूप में ढलने लगी है। मिदनिया

तिराहे से एसएसबी बटालियन होते हुए शहर सीमा तक चलने वाले इस अहम मार्ग पर ३ मीटर की पुरानी सड़क को बढ़ाकर ५.३० मीटर चौड़ी सीसी रोड बनाया जा रहा है। सड़क की दोनो ओर इंटरलॉक और नाली निर्माण भी प्रस्तावित है। यही नहीं, यह नई सड़क सीधे बाईपास से जुड़कर यातायात को नई रफ्तार देगी। शनिवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल स्वयं एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह और अफसरों की टीम के साथ मौके पर पहुँचीं और पूरे मार्ग का पैदल निरीक्षण किया। डीएम ने निर्माण गुणवत्ता, लेवलिंग, ढलाई, रोड कटिंग और कार्य की गति की गहन समीक्षा की और स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुणवत्ता में किसी भी स्तर पर समझौता स्वीकार नहीं होगा। निरीक्षण के दौरान डीएम ने सड़क निर्माण में बाधा बन रहे बिजली पोलों की शीघ्र शिफ्टिंग, सड़क किनारे अतिक्रमण हटाने, स्लैब की मजबूती और समयबद्ध कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंनेगौरतलब है कि डीएम की पहल पर मिदनिया तिराहे से एसएसबी के आगे तक गढ़ी मार्ग के चौड़ीकरण,सु ढ़ीकरण और नाली निर्माण का कार्य अवस्थापना विकास निधि व विकास शुल्क निधि से १.६४ करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। 'इनकी रही मौजूदगी' रू निरीक्षण में लोक निर्माण विभाग (प्रांतीय खंड) के अधिशासी अभियंता तरुणेन्द्र त्रिपाठी, विद्युत एक्सईएन शैलेंद्र कुमार, नायब तहसीलदार अश्विनी कुमार, प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह समेत पूरी राजस्व टीम मौजूद रही।

एसआईआर की सीमा बढ़ी

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने एक बार फिर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाई है। इस बार पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर की सीमा बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश को दो हफ्ते की मोहलत दी गई है। देश के सबसे बड़े राज्य में अब २६ दिसंबर तक मतदाता प्रपत्र भरा जा सकेगा। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने दो हफ्ते का समय बढ़ाने की मांग की थी। गुरुवार को चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में १८ दिसंबर तक फ र्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में २६ दिसंबर, जबकि गुजरात और तमिलनाडु में १४ दिसंबर तक फ र्म भरे जा सकेंगे। पहले फ र्म भरने की आखिरी तारीख ११ दिसंबर थी। आयोग ने बताया कि गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के लिए समय सीमा गुरुवार को ही समाप्त होगी और ड्राफ्ट मतदाता सूची १६ दिसंबर को प्रकाशित की जाएगी। गौरतलब है कि केरल में पहले ही डेडलाइन दो हफ्ते बढ़ा कर १८ दिसंबर कर दी गई थी। केरल की मसौदा मतदाता सूची २३ दिसंबर को प्रकाशित होगी। इससे पहले चुनाव आयोग ने सभी १२ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ३० नवंबर को एसआईआर की समयसीमा एक सप्ताह बढ़ाने का फैसला किया था। आयोग ने कहा था कि पहला चरण ११ दिसंबर

तक चलेगा और अंतिम मतदाता सूची १४ फरवरी २०२६ को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने बुधवार को एक और बड़ा ऐलान किया और कहा कि एसआईआर प्रक्रिया के तहत राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को मसौदा मतदाता सूची जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित वोटरों की सूची दी जाएगी। आयोग ने राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों को हर बूथ के हिसाब से अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट वोटरों की सूची तैयार कर बूथ एजेंट्स को देने का निर्देश दिया है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की संशोधित समय–सारिणी जारी

लखीमपुर खीरी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की संशोधित समय– सारिणी जारी कर दी गई है। अर्हता तिथि ०१ जनवरी २०२६ के आधार पर होने वाले इस महत्त्वपूर्ण कार्य के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जारी कार्यक्रम के अनुसार गणना अवधि एवं मतदान केंद्रों का सम्भाजनध्पुनर्व्यवस्था २६ दिसंबर २०२५ (शुक्रवार) तक पूर्ण किया जाएगा। इसके बाद २७ से ३० दिसंबर २०२५ तक कंट्रोल टेबल अपडेट करने तथा ड्राफ्ट रोल तैयार करने का कार्य होगा। निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन ३१ दिसंबर २०२५ (बुधवार) को किया जाएगा। दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि ३१ दिसंबर २०२५ से ३० जनवरी २०२६ तक निर्धारित की गई है। नोटिस फेजेंजिसमें नोटिस जारी करना, सुनवाई, वेरिफिकेशन एवं ईआरओ द्वारा एन्यूमरेशन फ र्म पर निर्णय तथा दावे और एक साथ आपत्तियों का निस्तारण शामिल है, जो ३१ दिसंबर २०२५ से २१ फरवरी २०२६ तक चलेगा। इलेक्टोरल रोल के हेल्थ पैरामीटर्स की जांच और अंतिम प्रकाशन हेतु आयोग से अनुमति प्राप्त करने की अंतिम तिथि २५ फरवरी २०२६ तय की गई है। इसके उपरांत २८ फरवरी २०२६ (शनिवार) को निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन होगा। निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में डीईओ, ईआरओध्एईआरओ सहित संबंधित अधिकारियों के पद रिक्त न रहें तथा उनका स्थानांतरण आयोग की पूर्व अनुमति के बिना न किया जाए। जिले के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना नाम मतदाता सूची में ऑनलाइन सर्च कर लें।

वंदे मातरम् का विवाद राजनीतिक है।

सात नवंबर को वंदे मातरम् की रचना के डेढ़ सौ साल पूरे हुए हैं। बंकिम चंद्र चटोपाध्याय ने सात नवंबर १८७५ को अक्षय नवमी के दिन इसकी रचना की थी। इसके सात साल बाद १८८२ में उन्होंने इस रचना को अपने उपन्यास 'आनंदमठ' में शामिल किया। बंकिम बाबू के निधन के दो साल बाद १८९६ में कांग्रेस के अधिवेशन में खुद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गाया। इसकी रचना दो हिस्सों में हुई और दोनों के संदर्भ भी अलग अलग हैं। बंकिम बाबू ने पहले दो ही अंतरे लिखे थे, जिसे आजादी के बाद राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया। पहले दो अंतरे लिखने के बाद उन्होंने 'आनंदमठ' की रचना की, जो उस समय के मुस्लिम शासकों के खिलाफ संन्यासियों के विद्रोह पर आधारित था। उसमें कई और अंतरे के साथ वंदे मातरम् को शामिल किया गया। चूंकि उपन्यास मुस्लिम शासकों के खिलाफ संन्यासी विद्रोह पर आधारित था तो स्वाभाविक रूप से उसमें मुस्लिम शासकों का विरोध है और हिंदू देवियों खासकर दुर्गा और लक्ष्मी का चित्रण है। वही चित्रण वंदे मातरम् के बाद के अंतरों में भी दिखता है। इसके बावजूद १८८२ से लेकर १९०६ तक यानी २७ साल तक किसी मुस्लिम नेता या धर्मगुरू की ओर से इसका विरोध नहीं हुआ। उलटे १९०५ में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन का फैसला किया तो वंदे मातरम् उसके विरोध का गीत बन गया। हिंदू और मुस्लिम दोनों बंगाल को अपनी मातृभूमि मानते थे और उसके विभाजन का विरोध करते थे। जहां भी अंग्रेजों की पुलिस उनको रोकने की कोशिश करती वहां वे वंदे मातरम् गाते थे। उस समय तक यह कौमी नारा था। किसी ने इसमें धार्मिकता का पुट नहीं देखा था। हैरानी की बात है कि बांटो और राज करो की नीति प्रतिपादित करने वाले अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था कि इसे धार्मिक नारा और धार्मिक गीत बना दिया जाए तो मुसलमानों को इससे अलग किया जा सकता है। तभी जब वे इस गीत और नारे की लोकप्रियता से परेशान हुए तो इस पर पाबंदी लगा दी और वंदे मातरम् बोलना मना कर दिया। लेकिन जो अंग्रेज शासक नहीं देख सके वह मुस्लिम लीग के नेता सैयद अली इमाम ने देख लिया। १९०६ में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। उसके तीन साल बाद १९०९ में सैयद अली इमाम और उनके कुछ साथियों ने वंदे मातरम् को धार्मिक गीत बताया और मुसलमानों से इससे दूर रहने की अपील की। सोचें, गीत लिखे जाने के ३४ साल बाद और पहली बार गाए जाने के १३ साल बाद कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं ने इसे धर्म गीत बताया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नए बने संगठन मुस्लिम लीग की राजनीति चमकाने के लिए ऐसा किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले दिन से मानते थे कि यह मुख्यधारा के मुस्लिम नेताओं या मुस्लिम आवाम का काम नहीं है, बल्कि सांप्रदायिक तत्वों ने इसे धार्मिक रंग दिया और राजनीति साधने का प्रयास किया। इस विवाद को समाप्त करने और इसे सबके लिए स्वीकार्य बनाने के मकसद से १९३७ में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले वंदे मातरम् के पहले दो अंतरे को राष्ट्रीय गीत चुना गया। आजादी के बाद संविधान सभा द्वारा भी वंदे मातरम् के पहले दो अंतरों को ही राष्ट्रीय गीत के तौर पर स्वीकार किया। यह सही है कि वंदे मातरम् को राष्ट्रगान जन गण मन की तरह संवैधानिक मान्यता नहीं मिली लेकिन भारतीयों के मन में इसके प्रति सम्मान में कभी कम नहीं हुआ। हालांकि एक बार शुरू होने के बाद हमेशा इसे लेकर राजनीतिक विवाद होते रहे हैं। अभी इसकी रचना के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर भी राजनीति ही हो रही है। राजनीतिक मकसद से

इस पर संसद में चर्चा कराई गई और राजनीतिक मकसद से ही इसका विरोध किया जा रहा है। वंदे मातरम् के अंतरे हटाने को इसे विभाजित करने वाला बताने और इसके देश विभाजन का कारण बनने का जो दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है वह भाजपा की राजनीति से जुड़ा है और उसका कोई ठोस आधार नहीं है। यह आरोप भी बेबुनियाद है कि जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम् के अंतरे हटवा दिए। यह एक सामूहिक फैसला था, जिसमें महात्मा गांधी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित नेहरू सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे। संविधान सभा ने भी जब इसे अपनाया गया तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल और पंडित नेहरू सहित उस समय की कांग्रेस के सारे नेता इस पर सहमत थे कि हर भारतीय के लिए स्वीकार्य बनाने के लिए जरूरी है कि पहले दो अंतरे ही स्वीकार किए जाएं। यह भी समझने की जरुरत है कि विभाजन की नींव दो राष्ट्र के सिद्धांत से पड़ी थी और वंदे मातरम् के अंतरे हटाने का उससे कोई लेना देना नहीं है। देश के लोगों को यह भी जानना चाहिए कि वंदे मातरम् की तरह जन गण मन भी एक लंबे गीत का छोटा सा हिस्सा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक लंबा गीत लिखा था, जिसके शुरुआती दो अंतरे राष्ट्रगान के तौर पर स्वीकार किए गए। दूसरी ओर मुस्लिम सांप्रदायिक नेताओं को वंदे मातरम् का विरोध राजनीतिक रूप से फायदेमंद दिख रहा था इसलिए उनको इसे स्वीकार ही नहीं करना था। तभी उन्होंने १९०६ में भी इसका विरोध किया और सभी अंतरे हटा कर सिर्फ दो अंतरे स्वीकार करने के १९३७ के फैसले के बाद भी इसका विरोध किया। आजादी के बाद भी इसका विरोध जारी रहा। अभी भी चाहे राजनीतिक दल एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी हों या सामाजिक संगठन जमीअत उलमा ए हिंद के नेता अरशद मदनी हों सबका विरोध राजनीतिक है। वास्तविकता यह है कि वंदे मातरम् के विरोध का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह भी समझने की जरुरत है कि इस गीत में जिसे माता कहा जा रहा है वह भारत माता नहीं हैं, बल्कि मातृभूमि है। यह गीत बुनियादी रूप से बंगाल के लिए लिखा गया था। तभी मूल गीत में 'सप्त कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, द्विसप्त कोटि भुर्जैत खरकर वाले' लिखा गया है। इसमें सात करोड़ कंठ और १४ करोड़ भुजाओं का जिक्र किया गया है। उस समय अविभाजित बंगाल की आबादी सात करोड़ के करीब थी। बाद में जब इसे राष्ट्रीय गीत बनाया गया तो 'सप्त कोटि' को 'कोटि कोटि' कर दिया गया। इसलिए यह किसी देवी या माता या किसी मूर्ति की पूजा का गीत नहीं है, बल्कि मातृभूमि की वंदना का गीत है। यह किसी धार्मिक मान्यता का हिस्सा नहीं है, बल्कि आजादी की लड़ाई और व्यापक रूप से भारत की संसेंति का हिस्सा है। लेकिन समय समय पर हिंदू और मुस्लिम दोनों में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोग इस पर विवाद उठा कर अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले संसद में इस पर चर्चा कराने और आधे अधूरे तथ्यों के आधार पर वंदे मातरम् के अंतरे हटाने के लिए कांग्रेस और उसमें भी खासतौर से पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराने का दयनीय प्रयास राजनीति से जुड़ा है तो ओवैसी और मदनी जैसे नेताओं के भड़काऊ बयान भी उनकी राजनीति का हिस्सा हैं। इनका धर्म और समाज से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबाओ सुबियांतो ने इसी साल संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया तो अरबी में 'अस्सालम आलेकुम' कहा तो साथ ही संस्कृत में 'ओम स्वस्तिअस्तु' भी कहा। सोचें, दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के सबसे बड़े नेता को सीधे तौर पर हिंदू धर्म से जुड़े 'ओम स्वस्तिअस्तु' का उच्चारण करने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन भारत के मुस्लिम नेताओं को आजादी का कौमी नारा वंदे मातरम् बोलने में दिक्कत है!

ईडी ने उत्तर प्रदेश से संबंधित अवैध कफ सिरप मामले में विभिन्न राज्यों में छापे मारे

लखनऊ। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश में अवैध कफ सिरप के व्यापार से जुड़े कथित गिरोह के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले की जांच के तहत शुक्रवार को विभिन्न राज्यों में छापे मारे। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर व सहारनपुर के अलावा झारखंड के रांची और गुजरात के अहमदाबाद में २५ स्थान पर छापे मारे गए। एजेंसी ने कथित अवैध व्यापार की जांच के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, फरार मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल और उसके कथित सहयोगियों आलोक सिंह, अमित सिंह और कुछ अन्य लोगों, कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) विष्णु अग्रवाल से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोडीन-युक्त कफ सिरप (सीबीसीएस) के दुरुपयोग, उनके अवैध उत्पादन, व्यापार और आपूर्ति से संबंधित घटनाओं पर संज्ञान लिया था, जिसके बाद पुलिस ने ३० से अधिक प्राथमिकियां दर्ज कीं। इन प्राथमिकियों के आधार पर ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में अपराध से अर्जित कुल कमाई करीब १,००० करोड़ रुपये है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के दुबई भाग जाने की आशंका है, जबकि उसके पिता को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य की पुलिस अब तक ३२ लोगों को हिरासत में ले चुकी है और इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है।

एमजीएनआरईजीए को लेकर प्रियंका गांधी का दावा, नाम बदलने में सरकार के बहुत सारे संसाधन होंगे खर्च

नई दिल्ला। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखने की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नाम बदलने की प्रक्रिया में सरकार के बहुत सारे संसाधन खर्च हो रहे हैं और यह अनावश्यक है। पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि एमजीएनआरईजीए योजना का नाम बदलने के पीछे का तर्क उन्हें समझ नहीं आ रहा है, जिससे अनावश्यक खर्च हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके पीछे क्या मानसिकता है। पहली बात तो यह महात्मा गांधी का नाम है, और जब इसे बदला जाता है, तो सरकार के संसाधन फिर से इस पर खर्च होते हैं। दफ्तरों से लेकर स्टेशनरी तक, सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है, इसलिए यह एक बड़ी और खर्चीली प्रक्रिया है। तो इस अनावश्यक काम का क्या फायदा? मुझे समझ नहीं आ रहा। आज सुबह शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एमजीएनआरईजीए योजना के संभावित

नाम परिवर्तन की खबरों पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए इसे जनता को गुमराह करने और गांधी परिवार के नाम का अपमान करने का ध्यान भटकाने वाला कदम बताया। बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा कि लोगों की निराशा के कारण ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं। यह ध्यान भटकाने का एक और तरीका है। वंदे मातरम के १५० वर्षों की चर्चा ने जनता को यह समझने में मदद की है कि इतिहास का कौन सा संस्करण व्हाट्सएप संस्करण है और कौन सा वास्तविक है। इसीलिए व्हाट्सएप पर विश्वास करने वाले लोग गांधी परिवार से नाराज होंगे। जो लोग सच्चा इतिहास जानते हैं, वे गांधी परिवार के योगदान के लिए हमेशा उनका सम्मान करेंगे। एमजीएनआरईजीए ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक रोजगार योजना है जो प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम १०० दिनों का गारंटीत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है। १८ वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की तारीख से १५ दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार प्राप्त होता है।

वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए जनवरी में शुरू होगी उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार अगले महीने स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार द्वारा शनिवार को यहां जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश में वायु प्रदूषण की बढ़ती चुनौती से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनवरी माह में उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन परियोजना (यूपीसीएएमपी) की शुरुआत करेंगे। बयान के अनुसार इस परियोजना के शासी निकाय की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव करेंगे जबकि प्रमुख सचिव और अपर मुख्य सचिव सदस्य के रूप में नामित होंगे। अधिकारियों के मुताबिक वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विश्व बैंक के सहयोग से यूपीसीएएमपी परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है। इसी क्रम में हाल ही में यूपीसीएएमपी प्राधिकरण के शासी निकाय की दूसरी बैठक मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के कार्यान्वयन से जुड़े सभी आवश्यक कदमों की समयबद्ध प्रगति की अद्यतन जानकारी आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए। बयान के मुताबिक इस परियोजना को लेकर तीन नवंबर को नयी दिल्ली में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), विश्व बैंक और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच परियोजना वार्ता सफलतापूर्वक संपन्न हुई थी। इसके बाद १० दिसंबर २०२५

को विश्व बैंक के निदेशक मंडल द्वारा परियोजना को औपचारिक मंजूरी प्रदान की गई। बयान के मुताबिक यूपीसीएएमपी भारत की अपनी तरह की पहली वायुक्षेत्र–आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन परियोजना है, जिसे सिंधु–गंगा के मैदानों में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों को लक्षित करते हुए एक बहु–क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में विकसित किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक यह परियोजना विश्व बैंक द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)–कानपुर, आईआईटी– दिल्ली और नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट फॉर एयर रिसर्च (एनआईएलयू) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से किए गए व्यापक वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित है। इसमें ऑस्ट्रिया के आईआईएएसए द्वारा विकसित गेन्स मॉडल का उपयोग किया गया है। उन्होंने बताया कि यूपीसीएएमपी पर कुल ३०४.६६ मिलियन डॉलर खर्च होंगे, जिसमें २६.६६ करोड़ डॉलर का ऋण (लगभग ४६,१८८ करोड़ येन के बराबर) और ५० लाख डॉलर का अनुदान शामिल है। इस परियोजना को वर्ष २०२५ से २०३१ तक छह वर्षों की अवधि में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। यह परियोजना उद्योग, परिवहन, कृषि, सड़क की धूल, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ खाना पकाने जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिससे उत्सर्जन में कमी के लिए एक समन्वित और प्रभावी रणनीति अपनाई जा सके। इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य वायुक्षेत्र आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ करना और विभिन्न क्षेत्रों में उत्सर्जन को कम करना है। बयान के मुताबिक इस योजना के तहत लगभग ३६ लाख परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के समाधान उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर में १५,००० इलेक्ट्रिक थ्री–व्हीलर और ५०० इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा दिया जाएगा, जबकि १३,५०० प्रदूषणकारी भारी वाहनों के प्रतिस्थापन के लिए प्रोत्साहन भी दिया जाएगा।

लखनऊ पहुंचेंगे 10 हजार रेलकर्मी : 22 व 23 दिसंबर को होगा अधिवेशन

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन और नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन का अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में भारतीय रेल के कर्मचारी पूरे देश से लखनऊ पहुंचेगे। इस अधिवेशन में रेलवे में बड़ी संख्या में रिक्त पड़े पदों, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, कार्य के दबाव, महिला कर्मचारियों की समस्याओं समेत अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। साथ ही इस अधिवेशन में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए रोड मैप भी तैयार होगा। यह अधिवेशन लखनऊ में २२ से २३ दिसम्बर को होना तय हुआ है। जिसमें इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के महासचिव स्टीफन क टन भी हिस्सा लेंगे। यह जानकारी एआईआरएफ के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने शनिवार को दी है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि रेलकर्मी देश की जीवनरेखा मानी जाने वाली भारतीय रेल को निरंतर सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन रेलकर्मियों की मांग आज भी लंबित है। उन्होंने बताया कि यह ऑल इण्डिया रेलवे मेन्स फेडरेशन का १०१वां व नार्दर्न रेलवे मेन्स यूनियन का ७७वां अधिवेशन है। इसके जरिये रेल कर्मचारियों और पेंशनरों से जुड़े मुद्दों पर केंद्र सरकार व रेलवे प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है, जिससे रेल कर्मियों की मांग जल्द से जल्द पूरी हो सके।...मांगें.... १. दिनांक २१.११.२०२५ को अधिसूचित नये श्रम कानूनों में व्याप्त विसंगतियों पर सम्बन्धित पक्षकारों से चर्चा कर संशोधन उपरान्त ही इसे लागू किया जाये।२. ८वें पे कमीशन के ज्मतउे वत्मिमितमदबम में गैर–वित्तीय एवं गैर–अंशदायी पेंशन के विषय को समाप्त किया जाये। ३. कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाये व इसे दिनांक ०१.११.२०२३ से लागू किया जाये। ४. रेल आवासों, कार्यालयों, रनिंग व रेस्ट रूम, सड़कों व नालियों की मरम्मत कर आवश्यक सुधार किये जायें। ५. नये कार्य रेल संरचनाओं के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाये। विभिन्न कोटियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाये संरक्षा से समझौता न किया जाये। ६. एकीकृत पेंशन योजना (यू.पी.एस.) में कर्मचारी अंशदान को मय ब्याज सेवानिवृत्ति पर भुगतान सुनिश्चित करते हुए योजना को कर्मचारी हित में किया जाये ७. गेटमैन, प्वाइंट्समैन समेत सभी श्रेणियों में काम के घंटों को अधिकतम ८ घंटे निर्धारित किया जाये। अतिरिक्त कार्य के एवज में ओवरटाइम भुगतान किया जाये। ८. महिला रेल कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव के दूसरे वर्ष में की जा रही २० प्रतिशत वेतन की कटौती के नियम को समाप्त किया जाये। ९. रेल कर्मचारियों के आश्रितों की नियुक्ति हेतु लार्सजेस योजना को बहाल किया जाये। १०. रनिंग कर्मचारियों हेतु ग्रेड पे रू. ४६००, ४८०० व ५४०० की व्यवस्था की जाये तथा माइलेज दरों में २५: कर दिनांक ०१ जनवरी, २०२४ से देय एरियर भुगतान किया जाये। ११. ट्रैकमेन्टेनर्स व प्वाइंट्समैन कोटियों में ग्रेड पे रु. ४२०० में न्यूनतम १० प्रतिशत पदों का सुजन किया जाये। १२. रेल कर्मचारियों के माता–पिता को रेलवे पास पीटीओ तथा चिकित्सीय सुविधाओं हेतु आभित माना जाये। १३. सभी बड़े स्टेशनों पर अराजपत्रित रेल कर्मचारियों हेतु विश्रामगृह्हों की सुविधा उपलब्ध करायी जाये। १४. अनुकम्पा के आधार पर मृतक आश्रितों को उनकी शैविक योग्यता एवं चिकित्सीय श्रेणी के अनुसार पद आवंटित किये जायें। १५. विभिन्न संस्था कोटियों में रिस्क एवं हार्ड ड्यूटी एलाउन्स में वृद्धि व इसके दावों में अन्य कोटियों को भी शामिल किया जाये।

बागपत में किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत जिले के बिहारीपुर गांव में शनिवार को एक किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, बागपत कोतवाली क्षेत्र के बिहारीपुर गांव में ऋषिपाल (५६) की गांधी चौक के पास किराना की दुकान है। परिजनों के मुताबिक, ऋषिपाल ने शनिवार सुबह करीब पांच बजे दुकान खोली थी। कुछ देर बाद पहुंचे दो बदमाशों ने सीने में गोली मारकर ऋषिपाल की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले तीसरे बदमाश ने घटना की रेकी की थी। पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि २० दिन पहले गांव के ही एक व्यक्ति से ऋषिपाल का विवाद हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

जाली दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे चार शिक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज

प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिले की महेशगंज थाना पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति के आरोप में चार शिक्षकों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी वृजनंदन राय ने शनिवार को बताया कि थाना महेशगंज स्थित शांभवी संस्थान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चितामनपुर पटना की प्रबंधक कलावती पाण्डेय ने शुक्रवार को तहरीर दी कि विद्यालय के प्रधानाचार्य पद से २०२१ में सेवानिवृत्त होने से पहले हरिश्चन्दर शुक्ला ने २०१७ में प्रबंधक का फर्जी हस्ताक्षर कर कूटरचित दस्तावेज के सहारे अपने बेटे शक्ति प्रकाश और अपनी परिचितों नंदनी देवी एवं खुशबू की सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की थी। कलावती ने आरोप लगाया कि सेवानिवृत्ति के बाद शुक्ला ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपने बेटे को २०२१ में विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया। राय ने बताया कि पुलिस तहरीर के आधार पर पूर्व प्रधानाचार्य हरिश्चन्दर शुक्ला, शक्ति प्रकाश, नंदनी देवी एवं खुशबू के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।

यूपी में ५ आईएएस अधिकारियों का तबादला रू चित्रकूट के CDO बने देवी प्रसाद पाल

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर प्रशासनिक ढांचे में फेरबदल हुआ है। शासन ने शनिवार को पांच आईएएस अधिकारियों का तबादला आदेश जारी किया है। चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी रहे राजेश कुमार को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस–वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं चित्रकूट के मुख्य विकास अधिकारी देवी प्रसाद पाल को बनाया गया है। देवी प्रसाद पाल इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के उपसचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।

सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने से हड़कंप

लखनऊ। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट का बताया जा रहा है। जिसमें सुरक्षा गार्ड की वर्दी में मौजूद कुछ लोग एक युवक को मारपीट कर उसे अपनी गाड़ी में बैठाते दिख रहे हैं। वहीं, एयरपोर्ट सूत्रों का कहना है कि एयरपोर्ट पर शुक्रवार सुबह नो–पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने को लेकर एक निजी कार चालक और एयरपोर्ट के निजी सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। लखनऊ निवासी कार चालक अपने एक दोस्त के साथ परिचित को रिसीव करने एयरपोर्ट आया था। उसने गलती से अपनी गाड़ी नो–पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर दी। इस पर तैनात निजी सुरक्षा गार्ड ने उसे वहां से गाड़ी हटाने को कहा। लेकिन कार चालक ने अपने परिचित को रिसीव कर तुरंत वहां से जाने की बात कही। इस पर सुरक्षाकर्मी नहीं माने और कार के पहिए में लॉक लगाने पहुंच गए। जिससे भड़के कार चालक और सुरक्षा गार्ड के बीच बहस हो गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मी ने अपने कई अन्य साथियों को बुलाकर कार चालक की पिटाई कर दी। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठा लिया और अपने अधिकारी के पास ले गए। जहां काफी देर तक चली बहस के बाद सख्त हिदायत देकर कार चालक को छोड़ दिया गया। पुलिस का कहना है कि अगर ऐसी कोई तहरीर मिली तो मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स एएनटीएफ को और मजबूत करने का निर्णय लिया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टॉस्क फोर्स (एएनटीएफ) को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में एएनटीएफ में पुलिस कर्मियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग में नियतन के हिसाब से फोर्स भी कम है। ऐसे में योगी सरकार ने एएनटीएफ को और मजबूत करने के लिए रेग्युलर पुलिस कर्मियों की तैनाती और नियतन के अनुसार फोर्स उपब्लध कराने का निर्णय लिया है। इससे जहां एएनटीएफ को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर अवैध नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी। एएनटीएफ आईजी अब्दुल हमीद ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध नशे पर नकेल कसने और ड्रग माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए वर्ष २०२२ में एएनटीएफ का गठन किया था। इस दौरान ६ थाने और ८ यूनिट का गठन किया गया। इन थानों में २८ पुलिसकर्मियों की तैनाती का नियतन रखा गया। इसमें एक निरीक्षक, ४ उपनिरीक्षक, ३ कंप्यूटर अ परेटर, ३ मुख्य आरक्षी, १२ आरक्षी, २ आरक्षी चालक और ३ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। इसी तरह यूनिट में

१८ पुलिस अधिकारियों समेत कर्मचारियों की तैनाती का नियतन रखा गया। इसमें एक पुलिस उपाधीक्षक, १ निरीक्षक, २ उप निरीक्षक, १ कंप्यूटर अ परेटर, २ मुख्य आरक्षी, ८ आरक्षी, २ आरक्षी चालक, २ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल हैं। बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया कि वर्तमान में एएनटीएफ में फोर्स को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया गया है। वहीं मानक के अनुरूप फोर्स भी नहीं है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों को एएनटीएफ में सभी पुलिसकर्मियों को रेग्युलर तैनाती के निर्देश दिये। साथ ही नियतन के अनुसार जल्द से जल्द फोर्स तैनात करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ड्रग माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए विभाग का गठन किया गया। ऐसे में उन्हे ड्रग माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए फोर्स के साथ आधुनिक उपकरण तत्काल उपलब्ध कराएं जाएं। आईजी ने बताया कि एएनटीएफ में पुलिस अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों की नियुक्ति का नियतन ३८६ है। इसमें राजपत्रित अधिकारी १५, मुख्यालय पर ५६, ६ थानों पर १६८, ८ यूनिट पर १४४ पदों पर तैनाती का नियतन है। वर्तमान में विभाग में २३६ पदों पर तैनाती की गयी है जबकि १५० पद खाली हैं। योगी के निर्देश के बाद जल्द सभी खाली पदों पर तैनाती की जाएगी।

दक्षिण कोरिया में पहली बार भारतीय फिल्म का कमाल, शांतनु माहेश्वरी की लव इन वियतनाम ने जीता दो अवार्ड

दिल्ली। 'लव इन वियतनाम' ने सियोल ग्लोबल मूवी अवार्ड्स २०२५ में दो पुरस्कार जीते। इसमें

'गंगूबाई काठियावाड़ी' से प्रसिद्ध शांतनु माहेश्वरी और 'टीकू वेड्स शेरू' में अभिनय के लिए जानी जाने वाली अवनीत कौर ने अभिनय किया है। इंडो– वियतनामी रोमांटिक ड्रामा फिल्म १२ सितंबर को भारत में रिलीज हुई, जिसके बाद यह आठ दिसंबर को कोरिया में भी रिलीज हुई। राहत शाह काजमी द्वारा निर्देशित यह फिल्म हिंदी सिनेमा में भारत–वियतनाम के पहले सहयोग का प्रतीक है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, फिल्म को एशिया की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला और निर्देशक काजमी ने एशिया के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। यह दक्षिण कोरिया में पहली बार किसी भारतीय फिल्म और फिल्मकार द्वारा दोनों पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड है। यह कार्यक्रम १० दिसंबर को आयोजित किया गया था। काजमी ने एक बयान में कहा, 'दक्षिण कोरिया से मिला यह सम्मान मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह साबित करता है कि अगर किसी कहानी को ईमानदारी से बताया जाए, तो वह दुनिया भर में लोगों के दिलों को छू सकती है।' माहेश्वरी ने कहा, 'दक्षिण कोरिया में दर्शकों को रोते, ताली बजाते और हमारी फिल्म से इतनी गहराई से जुड़ते देखना अविस्मरणीय है। उनके प्यार ने सचमुच मेरे दिल को छू लिया है।

लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने पवन सिंह को धमकी देने से इनकार

मुम्बई। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने पवन सिंह को धमकी देने से इनकार किया है। यह घटना भोजपुरी स्टार पवन सिंह के उस आरोप के कुछ दिनों बाद सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि गिरोह के सदस्यों ने उन्हें अभिनेता सलमान खान के साथ मंच साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी थी। हरि बॉक्सर नामक गैंगस्टर का बताया जा रहा एक अ डियो क्लिप सामने आया है जिसमें वह दावा कर रहा है कि सिंह ने बिना किसी धमकी के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। भोजपुरी गायक पर बिश्नोई गिरोह के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सिंह ने सुरक्षा पाने के लिए जानबूझकर यह मुद्दा उठाया होगा। ऑडियो में हरि बॉक्सर कह रहे है कि हम सब कुछ खुलेआम करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने पवन सिंह को कोई धमकी नहीं दी है। हालांकि, उस वीडियो में एक स्पष्ट संदेश था– सलमान खान के साथ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को धमकी नहीं दी जाएगी, बल्कि सीधे हमला किया जाएगा। गैंगस्टर ने कहा, ष्अगर कोई सलमान खान के साथ काम करता है, तो हम उसे धमकी नहीं देंगे, बल्कि एके–४७ की गोलियों से मार डालेंगे। सिंह ने दावा किया कि बिग बॉस १६ के फिनाले में सलमान के साथ परफॉर्म करने की घोषणा इंस्टाग्राम पर करने के बाद उन्हें कथित तौर पर धमकी मिली। भोजपुरी गायक ने यह भी दावा किया कि उन्हें पैसे की मांग करते हुए फोन आए। फोन करने वाले ने कथित तौर पर सिंह को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने सलमान के साथ स्क्रीन शेयर नहीं की तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इस सप्ताह की शुरुआत में, गायक ने मुंबई पुलिस में दो शिकायतें दर्ज कराईं। सिंह के मैनेजर ने गायक के लिए पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सिंह के सहयोगियों और उनकी टीम के कुछ सदस्यों को भी धमकी भरे संदेश मिले हैं। इन फोन नंबरों का पता बिहार और मुंबई से लगाया गया है।

लूलू की VIP पार्किंग में फायरिंगः शोरुम कर्मी का आरोप- मामले को दबाया

लखनऊ। सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में लूलू मॉल की वीआईपी पार्किंग में एक ज्वैलर्स शोरूम के कर्मी पर फायरिंग का मामला

प्रकाश में आया है। पीड़ित ने सिक्योरिटी मैनेजर और थाने के एक दरोगा पर मामला दबाने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की गुहार की है। कानपुर निवासी तनिष्क शुक्ला ने बताया कि वह मॉल में एक ज्वैलरी स्टोर में नौकरी करते हैं। ४ दिसंबर को दोपहर १२रू४० बजे गेट नंबर–४ से दाखिल होकर वीआईपी पार्किंग में पहुंचे। इस बीच एकाएक उनपर फायरिंग हुई। गोली पैर को छूते हुए निकल गई। मौके से खोखा बरामद हुआ। तनिष्क ने बताया कि वह खोखा लेकर पुलिस चौकी पहुंचे। वहां मौजूद दरोगा और सिक्योरिटी मैनेजर को खोखा और लिखित तहरीर देने के बाद वे इलाज के लिए चले गए। आरोप है कि आठ दिन बाद भी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। यही नहीं मामले को दबाया भी गया।

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर २५२.७० करोड़ रुपये कमाये

रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म "धुरंधर" ने बॉक्स ऑफिस पर २५० करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है। निर्माताओं ने शनिवार को यह जानकारी दी। "उरीः द सर्जिकल स्ट्राइक" के निर्देशन के लिए प्रशंसा अर्जित कर चुके आदित्य धर ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। यह फिल्म

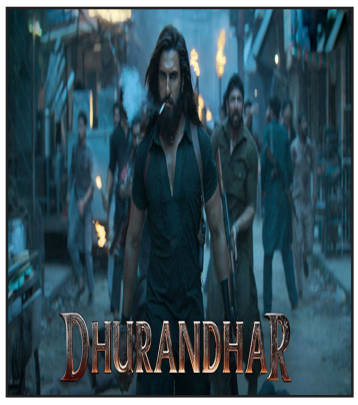

पांच दिसंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, आर माधवन और राकेश बेदी भी हैं। इस फिल्म का निर्माण धर और उनके भाई लोकेश धर ने अपने बैनर बी६२ स्टूडियोज के माध्यम से जियो स्टूडियोज की ज्योति देशपांडे के साथ मिलकर किया है। फिल्म निर्माता कंपनी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम हैंडल पर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े साझा किए। सोशल मीडिया मंच पर की गई एक पोस्ट में फिल्म के पोस्टर के ऊपर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े लिखे गए थे। फिल्म ने कुल २५२.७० करोड़ रुपये अर्जित किए हैं। यह फिल्म अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित है।

हमारे अन्य प्रतिनिधि
संजय बाजपेई
सीतापुर
मो.9935160370
प्रियंका त्रिपाठी
नई दिल्ली
विधिक सलाहकार
सुरेश नारायण मिश्र
क्षेत्रीय सम्पादक
सौरभ कुमार, बिहार
मो.09386075289
मो० अरशद
ब्यूरो चीफ
मऊ

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय द्वारा सांई आफसेट प्रिन्टर्स, 40 वासुदेव भवन भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के पीछे, कैसरबाग लखनऊ से छपवाकर एमआईजी 2/379 रश्मिखंड शारदानगर आशियाना लखनऊ उ0प्र0 से प्रकाशित।
आर.एन.आई
UPHIN/2010/32566

सम्पादक
आरती पाण्डेय
मो.9415087228
9889745884. 9807059191. 9026560178

Email-
adbhutsamachar@yahoo.in
adbhut_samachar@rediffmail.com
सभी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ होगा।

समाचार पत्र में छपी समस्त प्रकार की खबरों एवं लेखों का स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व सम्पादक आरती पाण्डेय से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। समाचार पत्र में छपी खबर एवं लेख पत्रकारों के अपने निजी विचार हैं। समाचार पत्र से जुड़े समस्त पत्रकारों के पद अवैतनिक हैं। और वह सब स्वतंत्र पत्रकार हैं। प्रकाशक/सम्पादक